उत्तर प्रदेश के किसानों को सीधे लाभ हेतु होगा व्यापक दुग्ध विकास

- *लखनऊ, कानपुर, वाराणसी एवं सैफई में स्थापित होंगी अमूल दूध उत्पादन इकाइयाँ*
- *प्रत्येक इकाई की क्षमता प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध उत्पादन की होगी*
- *कृषकों को सीधा लाभ–7 लाख से अधिक किसान परिवारों को होगा लाभ*
- *गाँवों में सहकारी संकलन केन्द्रों पर नगद भुगतान कर किसानों से खरीदा जाएगा दूध*
- *वर्ष के अन्त में लाभांश स्वरूप किसानों को बोनस भी मिलेगा*

लखनऊ, 16 दिसम्बर 2013

भारत में सबसे अधिक मवेशी एवं सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में डेयरी उद्योग वह मुकाम नहीं प्राप्त कर पाया है जिसकी यहाँ पर सम्भावनाएं विद्यमान हैं। कृषि प्रधान राज्य में डेयरी उद्योग के क्षेत्र में विद्यमान असीम सम्भावनाओं को साकार करने के लिए राज्य सरकार, और विशेष रूप से प्रदेश के मा. मुख्यमंत्री, श्री अखिलेश यादव जी, की पहल पर उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर विश्व–विख्यात् ब्राण्ड 'अमूल' के दुग्ध उत्पाद संयंत्रों की स्थापना की जाएगी।

इस कड़ी में प्रतिदिन 5 लाख लीटर दुग्ध उत्पादन क्षमता की चार इकाइयाँ स्थापित कराई जाएंगी। ये इकाइयाँ लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पर चकगंजरिया प्रक्षेत्र, जनपद कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र जैनपुर में, जनपद वाराणसी में एयरपोर्ट के समीप वाराणसी–लखनऊ राज्यमार्ग पर औद्योगिक क्षेत्र करखींआव एवं जनपद इटावा में सैफई में स्थापित की जाएंगी।

उल्लेखनीय है कि इससे राज्य के लाखों पशुपालकों व किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। जहाँ एक ओर पशुपालकों को उनके दुग्ध उत्पादों का उचित मूल्य मिलेगा, वहीं प्रदेश के नागरिकों व विशेष रूप से बच्चों को उच्च गुणवत्ता के दूध तथा दूध से निर्मित उत्पाद भी सुलभ हो सकेंगे।

प्रत्येक दुग्ध उत्पाद इकाई में रु. 150 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश होगा तथा अप्रत्यक्ष रोज़गार के अतिरिक्त इन संयंत्रों में प्रत्यक्ष रूप से 20,000 से अधिक नये रोज़गार सृजित होंगे। चारों इकाइयों के स्थापित हो जाने पर 7 लाख से अधिक कृषक परिवारों को सीधा लाभ होगा।

योजनानुसार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु चलाई जा रही कामधेनु योजना से समन्वय करते हुए प्रत्येक इकाई द्वारा 100 किमी. के क्षेत्र में स्थित गाँवों में सहकारी दुग्ध संकलन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। जिनमें किसानों को नगद भुगतान कर दूध खरीदा जाएगा। इतना ही नहीं वर्ष के अन्त में अर्जित लाभ में से लाभांश के रूप में किसानों को दुग्ध मूल्य के अतिरिक्त बोनस का भुगतान भी किया जाएगा।

इसके बाद प्रदेश के अन्य पिछड़े क्षेत्रों में पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड में भी कृषि–आधारित वृहद् उद्योग स्थापित किए जाने की योजना है।

————————————